(घ) क्या सरकार इस कार्य को टी०एच०डी०सी० की जगह उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) टिहरी जल विद्युत परियोजना द्वारा पूर्णतः प्रमाणित ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास प्रक्रिया टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन (टीएचडीसी) द्वारा दो चरणों में सम्पादित की जा रही है। पुनर्वास प्रक्रिया के चरण-I में काफर बांध के निर्माण द्वारा प्रभावित ग्रामीण परिवार शामिल हैं और चरण—II में मुख्य बांध के निर्माण द्वारा प्रभावित परिवार शामिल हैं। चरण-I के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को पुनर्स्थापना लगभग पूरा हो गया है और प्रभावित परिवारों को अब भूमि आवंटन के माध्यम से या इसके बदले में नगद भुगतान के माध्यम से प्रभावित परिवारों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर पुनर्वासित किया गया है। टीएचडीसी ने चरण-II में शामिल शेष ग्रामीण परिवारों की पुनर्स्थापना हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए अब कार्रवाई आरम्भ कर दी है और 2000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित शेष भूमि को अभिजात और अधिग्रहित करने के लिए भी कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(ग) जी, हां। प्रभावित लोगों ने प्रस्तावित नये राज्य की परिधि के भीतर आने वाले क्षेत्रों में स्वयं को पुनर्वासित करने का अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना पूर्णतः सम्मिलित है। तथापि राज्य सरकार को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित कार्य सौंपने का विचार किया गया है।

Commercial Losses To SEBs

3134. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the commercial losses of all SEBs put together were Rs. 4955 crores in March 1994 and increased Rs. 7130 crores in 1996 manly because of low rates and collection; and

(b) if so, how does Government plan to resolve this problem?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) As per the statement of Accounts received in the Central Electricity Authority (CEA) the commercial losses of all SEBs put together were Rs. 3018.91 crores (without subsidy) in 1993-94 and in 1995-96 the same increased to Rs. 6748.68 crores (without subsidy). One of the main reasons for the commercial losses of SEBs has been poor realisation of revenue per unit vis-a-vis cost of supply to consumers. Other reasons for poor financial health of SEBs are:—

(i) tariff structure is not rational

(ii) low plant load factor operation of thermal plants in some SEBs

(iii) high T&D losses

(iv) heavy interest burden arising from the capital structure of SEBs due to inadequate equity participation.

(b) The establishment of the Regulatory Commissions, as provided in the Act recently passed by the Parliament, would help in rationalising tariff and also provide for cross-subsidies, wherever required. The State Governments can exercise the option of providing subsidies, over and above, those recommended by the Regulatory Commissions. Such subsidies could cover free power to agriculture, and/or to weaker sections on condition that the State Governments compensate the SEBs by providing adequate budgetary support. When tariffs are rationalised and budgetary support is provided, the SEBs will improve their financial health and their capacity to invest.

Allocation of Naptha for Rajasthan

3135. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any request from the State Government of Rajasthan has been